(ख) और (ग) हालांकि, शत-प्रतिशत कार्यकुशलता दर व्यावहारिक नहीं है, तथापि ऐसे सभी प्रयास किए जाते हैं कि मदों के निपटान में विलम्ब कम से कम हों। शिकायतों के विश्लेषण से यह पता चला है कि विलम्ब मुख्यतः रेलवे और एयरलाइंस जैसी डाक-परिवहन एजेंसियों के कारण होता है। विलम्ब का एक नगण्य प्रतिशत निःसंदेह डाक-सेवा में निहित दोषों के कारण भी है। ऐसे सभी मामलों में अनिवार्यतः सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

Splitting of Indian Telephone Industries

2504. SHRI SUNIL BASU RAY:
SHRI RAMNARAYAN GOSWAMI:

Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Government are considering to split Indian Telephone Industries and to bring about major changes in the Hinustan Cables Corporation by way of reforms;

(b) if so, whether the transformation plan for the Hindustan Cable Corporation is progressing as per schedule; and

(c) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SUKH RAM): (a) No, Sir, there is no proposal of the Government to Split Indian Telephone Industries. Regarding Hindustan Cables Ltd. (HCL), in order to meet the challenges of fast product obsolescence, HCL has already undertaken certain product reconversion schemes.

(b) and (c) The implementation for HCL is progressing satisfactorily. HCL is also contemplating to diversify its range of product by taking up certain new projects and necessary steps are being taken towards this end.

Permission to allow private sector to install and operate rural and automatic Telephone Exchanges (RAXs)

2505. SHRI MATANG SINGH: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether the Department of Communications has decided to allow private sector to install and operate rural automatic telephone exchanges (RAXs);

(b) if so, what are the details of the decision taken along with the proposals under consideration/approved, so far;

(c) what are the details of steps being taken during the Eighth Five Year Plan for development of Telecommunications network-both in Public and Private sector separately, with details of order of investment proposed state-wise and the number of villages to be covered; and

(d) what steps are being taken to attain self-reliance in telecommunication equipment|machinery and develop export potential in the next 5 years?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SUKH RAM): (a) Proposal is under consideration.

(b) Does not arise.

(c) The Planning Commission has approved an outlay of Rs. 23946 Crores for 8th Five Year Plan of the Department of Telecommunications against the funds requirement of Rs. 40555 Crores for providing 75 lakhs new telephone connections and public telephones in about 3.8 Lakh villages. Options to raise the balance resources are under examination, but the expected additionality of resources cannot be quantified at this stage.

(d) Sufficient capacity already exists in the area of Rural Automatic Exchanges required for providing Rural Telecom. Exports of Rural Automatic Exchanges has also started and is expected to grow since the production capacity of these exchanges is much more than the requirements of the Department.

नयी टेलीफोन निर्देशिका के प्रकाशन के मानदण्ड

2506. **श्री अजीत जोगी :**
चौधरी हरि सिंह :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नई टेलीफोन निर्देशिका प्रकाशित करने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि नई टेलीफोन निर्देशिका के प्रकाशन में सदैव विलम्ब होता है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) उन शहरों के नाम क्या हैं जहां नई टेलीफोन निर्देशिका दो वर्ष से भी अधिक समय से प्रकाशित नहीं हुई है; और

(ङ) नई टेलीफोन निर्देशिका को कब तक प्रकाशित किए जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) अंग्रेजी में टेलीफोन निर्देशिकाएं सेंकेण्डरी स्विचन क्षेत्रवार वर्ष में एक बार प्रकाशित की जाती हैं । उचित मांग होने पर इनका प्रकाशन हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में भी किया जाता है लेकिन यह मांग टेलीफोन निर्देशिकाओं की कुल आवश्यकता का लगभग 15% होनी चाहिए ।

(ख) और (ग) जी नहीं । तथापि बहुत थोड़े से मामले में निविदाओं को अंतिम रूप देने और ठेका प्रदान करने में हुए विलम्ब तथा ठेकेदारों द्वारा समय पर आपूर्ति न करने के कारण टेलीफोन निर्देशिकाओं के प्रकाशन में विम्लब हुआ है ।

(घ) अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ङ) टेलीफोन निर्देशिकाओं के समय पर प्रकाशन हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।

मध्य प्रदेश मंडल में शाखा-डाकघर

2507. **श्री अजीत जोगी :**
चौधरी हरि सिंह :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश मंडल के अन्तर्गत इस समय कितने शाखा डाकघर कार्य कर रहे हैं; और

(ख) राज्य में नये शाखा डाकघर खोलने हेतु कितने आवेदन विचाराधीन हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) मध्य प्रदेश में इस समय कार्यरत शाखा डाकघरों की संख्या 9629 है ।

(ख) मध्य-प्रदेश में नए शाखा डाकघर खोलने के संबंध में विचाराधीन आवेदनों की संख्या 29 है ?

संसद सदस्यों की सिफारिश पर दिए गए टेलीफोन कनेक्शनों के मामले में कदाचार

2508. **श्री शंकर दयाल सिंह :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्यों की सिफारिश पर टेलीफोन कनेक्शन जारी किए जाने